

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 14
TO BE ANSWERED ON 22.07.2024

Green Credit Programme

14. SHRI CHUDASAMA RAJESHBHAI NARANBHAI:
SHRI PRADEEP KUMAR SINGH:
SHRI SATPAL BRAHAMCHARI:
SHRI DHARAMBIR SINGH:
SHRI Y S AVINASH REDDY:
SHRI JAGDAMBIKA PAL:
DR. RAJEEV BHARADWAJ:
SHRI MANOJ TIWARI:
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB:

Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

- (a) the details and status of the implementation of Green Credit Programme (GCP) in the country, State-wise including the details of Himachal Pradesh, district wise;
- (b) the main objectives and expected results of the GCP;
- (c) the details of the specific areas and activities identified under GCP;
- (d) the details of the norms laid down for registration, fund release and monitoring of works under Green Credit activities;
- (e) the details of the progress made under Green Credit programme in the country especially States of Bihar and Haryana particularly in Araria and Sonipat Parliamentary Constituencies;
- (f) whether the Government has introduced any programmes to increase awareness regarding the Green Credit initiative; and
- (g) whether any initiatives have been taken/proposed to be taken to make aware the environmentally friendly habits in the State of Uttar Pradesh?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
(SHRI KIRTI VARDHAN SINGH)

- (a) to (g). The Central Government has notified Green Credit Rules, 2023 on 12th October 2023 under the Environment Protection Act, 1986 to encourage voluntary environmental positive actions resulting in issuance of Green Credits.

To begin with, voluntary tree plantation/eco-restoration is envisaged on degraded land under the control and management of Forest Departments. The Ministry published

notification for 'Methodology for calculation of green credit in respect of tree plantation' on 22nd February 2024 (Annexure - I).

State Forest Department of every State/Union Territory identifies degraded land parcels under the control and management of Forest Department, which are made available for tree plantation/eco-restoration for the purpose of generation of green credits.

Green Credit Programme (GCP) Portal (<https://moefcc-gcp.in/>) has been developed to enable registration of Forest Department/plantation land blocks/entity, selection of land parcels by entity, demand note generation, payment by entity, issuance of green credits and monitoring. Details of guidelines for registration of state implementing agency, plantation blocks and financial and accounting procedure are provided in Annexure - II. Modality for monitoring of tree plantation/eco-restoration have been issued to States/UTs.

The Ministry has undertaken deliberations/interactions with Central Ministries/Departments, experts, industry, research and academia and other stakeholders for the Green Credit Programme. GCP portal has been developed and made accessible for everyone. URL: <https://www.moefcc-gcp.in/>

Status of registration of plantation blocks under GCP as on 16th July 2024 is provided in Annexure - III.

Ministry has launched Mission LiFE (Lifestyle for Environment) with aim to promote an environmentally conscious lifestyle and nudging individuals to undertake simple, climate-friendly actions in their daily lives. Awareness generation and outreach activities on Mission LiFE have been undertaken by several Ministries/Departments in order to sensitise the public at large. To increase the awareness among people and encourage them to adopt environment- friendly lifestyle, the Ministry is implementing various programs such as Environment Education Programme (EEP) and Environmental Information Awareness Capacity Building and Livelihood Programme (EIACP). The Ministry is implementing Environment Education, Awareness and Training (EEAT) scheme with the objective *inter-alia* to promote environmental awareness and mobilize students' participation for environment conservation.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022024-252377
CG-DL-E-26022024-252377

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 844]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 2024/फाल्गुन 7, 1945

No. 844]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 2024/PHALGUNA 7, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2024

का.आ. 884(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6, 25 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 12 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4458 (अ) द्वारा प्रकाशित ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम रूप में कहा गया है) बनाए थे;

और, उक्त नियमों के नियम 5 में उपबंध है कि केंद्रीय सरकार, प्रशासक की सिफारिश पर, उक्त नियमों के अधीन की गई किसी भी क्रियाकलाप के संबंध में ग्रीन क्रेडिट की गणना के लिए कार्यप्रणाली को अधिसूचित करेगी;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अनुसरण में, प्रशासक की सिफारिश पर, वृक्षारोपण के संबंध में ग्रीन क्रेडिट की गणना के लिए निम्नलिखित पद्धति को अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

1. प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के वन विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन खुले वन और झाड़ीदार भूमि, बंजर भूमि और जलग्रहण क्षेत्रों सहित अवक्रमित भूमि क्षेत्र की अभिज्ञात करेंगे, जिन्हें वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उक्त नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट के सृजन के प्रयोजनों के लिए देश भर में हरित आवरण की वृद्धि करने के लिए क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया जा सके।

2. पैरा 1 के अधीन वृक्षारोपण के लिए पहचान किए गए भूमि क्षेत्र को सभी ऋणधारों से मुक्त होना चाहिए और इसका आकार पांच हेक्टेयर या उससे अधिक होना चाहिए।
3. ग्रीन क्रेडिट के सृजन के प्रयोजनों के लिए वृक्षारोपण करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति या संस्था प्रशासक को आवेदन कर सकती है।
4. पैरा 3 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, प्रशासक पैरा 1 में निर्दिष्ट किसी भी भूमि की पहचान करेगा और आवेदक को सौंपेगा और उसे उक्त नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट के सृजन के लिए वृक्षारोपण करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहेगा।
5. पैरा 4 के अधीन प्रस्ताव प्राप्त होने पर, प्रशासक एक डिमांड नोट तैयार करेगा और उसे आवेदक को जारी करेगा, जिसमें वृक्षारोपण की लागत और प्रशासनिक व्यय, यदि कोई हो, को डिमांड नोट में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रशासक को भुगतान किया जाना सम्मिलित होगा।
6. आवेदक बैंक ड्राफ्ट या भुगतान के ऐसे अन्य साधनों, जो प्रशासक द्वारा तय किया जाए, के माध्यम से डिमांड नोट में निर्दिष्ट अवधि से पहले प्रशासक को राशि का भुगतान करेगा।
7. पैरा 6 के अधीन राशि के भुगतान पर, प्रशासक वन विभाग को प्रबंधन योजना या कार्य योजना के अनुरूप वृक्षारोपण करने का निदेश देगा और भुगतान की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर वृक्षारोपण कार्य पूरा किया जाएगा।
8. वृक्षारोपण पूरा होने पर, वन विभाग इस संबंध में प्रशासक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और आवेदक को वृक्षारोपण पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी करेगा।
9. पैरा 8 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्रशासक, वृक्षारोपण के मूल्यांकन और सत्यापन के पश्चात्, उक्त नियमों के अधीन निर्दिष्ट भूमि क्षेत्र में लगाए गए वृक्षों की कुल संख्या और वृक्षारोपण क्रियाकलाप के पूरा होने की रिपोर्ट और प्रमाणन के आधार पर ग्रीन क्रेडिट सृजित कर सकता है और आवेदक को जारी कर सकता है।
10. ग्रीन क्रेडिट की गणना संबंधित वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के पूरा होने के संबंध में किए गए प्रमाणन के पश्चात्, स्थानीय वृक्ष-जलवायु और मिट्टी की स्थितियों के आधार पर प्रति हेक्टेयर 1100 वृक्षों के न्यूनतम घनत्व के अधीन ऐसे भूमि क्षेत्र पर वृक्षारोपण के माध्यम से उगाए गए प्रति वृक्ष के लिए एक ग्रीन क्रेडिट की दर से की जाएगी।
11. उक्त नियमों के अधीन सृजित ग्रीन क्रेडिट का आदान-प्रदान वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), यथास्थिति, के अधीन गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अपवर्तन के मामले में प्रतिपूरक वनीकरण के अनुपालन को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।
12. उक्त नियमों के अधीन वृक्षारोपण के बदले में सृजित ग्रीन क्रेडिट का उपयोग पर्यावरण, सामाजिक और शासन नेतृत्व संकेतक के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत रिपोर्टिंग के लिए किया जा सकता है।

[फा. सं. एचएसएम-12/24/2023-एचएसएम (पीटी 2)-पार्ट (1)]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd February, 2024

S.O. 884(E).— Whereas, the Central Government made the Green Credit Rules, 2023 (hereinafter referred to as the said Rules) under section 3, 6, 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) vide notification number S.O. 4458(E), dated the 12th October, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii);

AND WHEREAS, rule 5 of the said Rules provides that the Central Government shall, on the recommendation of the Administrator, notify the methodology for calculating the green credit in respect of any activity undertaken under the said Rules;

NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-rule (1) of rule 5 of the Green Credit Rules, 2023, the Central Government, on the recommendation of the Administrator, hereby notifies the following methodology, for calculation of green credit in respect of tree plantation, namely: -

1. The Forest Department of every State and Union territory shall identify degraded land parcels, including open forest and scrub land, wasteland and catchment areas, under their administrative control and management, which shall be made available for tree plantation to promote activities for increasing the green cover across the country for the purposes of generation of Green Credit under the said Rules.
2. The land parcel identified for plantation under paragraph 1 must be free from all encumbrances and must have size of five hectares or above.
3. Any person or entity desirous of undertaking tree plantation for the purposes of generation of Green Credit may apply to the Administrator.
4. On receipt of the application under paragraph 3, the Administrator shall identify any land referred to in paragraph 1 and assign the same to the applicant and require him to submit a proposal for undertaking tree plantation for generation of Green Credit in lieu thereof under the said Rules.
5. On receipt of the proposal under paragraph 4, the Administrator shall prepare and issue a demand note to the applicant which shall include the cost of tree plantation and administrative expenses, if any, to be paid to the Administrator within a period specified in the demand note.
6. The applicant shall pay the amount to the Administrator on or before the period specified in the demand note through a bank draft or such other means of payment as may be decided by the Administrator.
7. On the payment of the amount under paragraph 6, the Administrator shall direct the Forest Department to carry out tree plantation in line with the management plan or working plan and shall be completed within a period of two years from the date of payment.
8. On completion of tree plantation, the Forest Department shall submit a report in this regard to the Administrator and issue a certificate of completion of tree plantation to the applicant.
9. On receipt of the report under paragraph 8, the Administrator, after evaluation and verification of the tree plantation activity may generate and issue Green Credit to the applicant under the said Rules, based on the total number of trees planted in assigned land parcel and on the report and certification of completion of tree plantation activity.
10. The Green Credit shall be calculated at the rate of one Green Credit per tree grown through the tree plantation on such land parcel, subject to minimum density of 1100 trees per hectare, based on the local silvi-climatic and soil conditions, on the certification of completion of tree plantation provided by the Forest Department concerned.
11. The Green Credit generated under the said Rules, may be exchanged for meeting the compliance of the compensatory afforestation in case of diversion of forest land for non-forestry purposes under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980), as applicable.
12. The Green Credit generated in lieu of tree plantation under the said Rules may be used for reporting under environmental, social and governance leadership indicator or under corporate social responsibility under the applicable rules made under any law for the time being in force.

[F. No. HSM-12/24/2023-HSM(pt2)-Part(1)]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.

Guidelines for registering an Implementing Agency (Forest Department)

1. Access Registration Form:

- click on Register on the portal: <https://www.moefcc-gcp.in/>
- Select user type as Implementing Agency (Forest Department).

2. Fill in Implementing Agency Information:

- Enter the name of the office of forest department in the designated text field. Eg PCCF Madhya Pradesh
- Select the State/UT from the dropdown menu, in this case Madhya Pradesh
- Provide the address of the head office in the text field provided.

3. Enter Bank Account Details:

- Name of Bank: Enter the name of the bank in the text field.
- Account Number: Input the account number in the numeric field.
- IFSC Code: Fill in the IFSC code in the text field.
- Attach a copy of the cancelled cheque using the attachment field provided.

4. Provide Nodal Officer Information:

- Enter the name of the Nodal Officer in the text field.
- Specify the designation of the Nodal Officer in the text field.
- Input the optional landline contact number of the Nodal Officer in the numeric field.
- Enter the mobile contact number of the Nodal Officer in the numeric field (mandatory)
- Provide the email address of the Nodal Officer in the email field (mandatory)

5. Add District Implementing Officers:

- Click on the option to add multiple District Implementing Officers.
- For each District Implementing Officer, fill separately:
 - Enter their name in the text field.
 - Specify their designation in the text field.
 - Input the district they are assigned to in the text field.
 - Provide the division they are assigned to in the text field.
 - Enter the landline contact number of the District Implementing Officer in the numeric field (optional).

- Input the mobile contact number of the District Implementing Officer in the numeric field.
- Provide the email address of the District Implementing Officer in the email field.

6. Submit Registration:

- Once all information is filled in accurately, submit the registration form.

7. Confirmation of registration

The registration details will go to ICFRE which will approve the registration. Once confirmed, , a confirmation message should pop up confirming the registration. An email will also be sent to the provided email address with the details of the registration.

This completes the registration process for the Implementing Agency (Forest Department), along with the submission of details for the Nodal Officer and District Implementing Officers.

Guidelines for registration of a Plantation Block by an Implementing Agency

1. Login:

- Access the portal (<https://www.moefcc-gcp.in/>) using the registration details received on mail.

2. Register Plantation Blocks: a) Enter the details of the plantation block:

- Enter State name (from drop-down menu)
- Select District name (from drop-down menu)
- Input the Area in hectares (must be at least 5 hectares)
- Fill in Division, Range, Tree canopy density (mandatory)
- Input Beat, and Compartment number (as alphanumeric fields) (Optional)

b) Enter Baseline Data(Optional):

- Edaphic Details: Soil type, Average soil depth, etc. (up to 200 words)
- Slope and Terrain Characteristics: Slopy, Plain, hilly, undulating, other, etc. (up to 200 words)
- Geological Features (up to 200 words)
- Hydrological Conditions: Rainfall, presence of water source, drainage, etc. (up to 200 words)
- Forest Type (up to 200 words)

c) Upload Required Documents:

- KML file , mandatory
- Geotagged Photos of the Proposed Location (minimum 3 photos) [Optional]

d) Complete the Forest Department Undertaking:

- Confirm if the land is free from all types of encumbrances (tick box - yes/no)
- Confirm if the land is suitable for plantation (tick box - yes/no)

3. Submit Information:

- After verifying all the entered information, click the "Submit" button.

4. Confirmation:

- Upon submission, a pop-up message appears confirming registration will be complete after Administrator Verification.
- Additionally, an email containing land registration details is sent to the registered email address of SNO and DIO.

F. No. HSM-12/24/2023-HSM(pt2)-Part(1), E-220847
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
HSM Division

6th Floor, Jal Wing
Indira Paryavaran Bhawan
Jor Bagh Road
New Delhi - 110003

Dated: 10th July, 2024

Office Memorandum

Subject: Guidelines on financial and accounting procedures, fund flow mechanism, record keeping and auditing under eco-restoration of degraded forests component under Green Credit programme - reg.

The detailed modalities for implementation of the tree plantation component under Green Credit Program (GCP) has been communicated vide O.M No. HSM-12/24/2023-HSM (PT2)-Part(i), E-220847 dated 22nd February 2024. A GCP Portal (<https://moefcc-gcp.in/>) has been developed to enable end to end implementation of the tree plantation component, including, registration of land parcels by state forest department, verification and approval of land parcels by Administrator (ICFRE), selection of land parcels by entities, submission of cost estimates, demand note generation etc.

2. The following financial and accounting procedures may be followed by Administrator (ICFRE) and State Forest Departments:

I. Fund disbursement to the State Forest Department:

- i. Separate saving account in a nationalized bank shall be opened and maintained for Green Credit Programme by the Administrator, State Nodal Officer (SNO), Implementing Officer (IO) and concerned Range Forest Officer.
- ii. After receipt of the funds from the entity, the concerned SNO will submit requisition for release of funds annually to the GCP Administrator on the

- GCP portal. The fund release requisition can also be submitted by the SNO to the GCP Administrator through email till the fund requisition interface is developed on the GCP portal.
- iii. After receipt of requisition for fund release, the administrator will scrutinize the request and thereafter release the funds to the SNO.
 - iv. Subsequent release of funds to the SNO will be done in annual instalments, as per the progress of the plantation work as per the OM No. 1-20/2023-RT dated 23.02.2024 issued by MoEF&CC. The release will be subject to submission of utilization certificates, progress reports and other relevant documents duly signed by the authorized officer in the States and UTs.
 - v. Administrator will upload sanction letter and transaction details on GCP portal immediately upon release of funds.
 - vi. The funds will be utilized by the State Forest Department by following prescribed financial procedures and rules adopted by the respective UT/ State Government, including administrative and financial sanctions as per delegation of powers.
 - vii. Utilization certificates, expenditure statement and physical progress reports shall be submitted by the SNO to the Administrator on the last fund release prior to release of any subsequent instalments.
 - viii. Administrator (ICFRE) should ensure adequate safety and safeguard mechanism for validity and data integrity in the GCP Portal.
 - ix. The activities of the Administrator, designated agency, Registry, trading platform and knowledge and data platform shall be audited within a period of one year at the end of every third financial year by independent auditors to be appointed by the Central Government on the recommendation of the Steering Committee.
 - x. The auditor referred to in sub-rule (1) of the Green Credit Rule 2023 shall submit its audit report to the Administrator. The Administrator shall submit an action taken report on the audit report to the Central Government within a period of six months from the date of the receipt of the audit report.

II. Financial and Accounting procedures

- i. The Administrator shall engage a Chartered Accountancy firm which is duly empaneled by the Comptroller and Auditor General of India for undertaking

proper accounting mechanisms and maintaining financial transparency. All necessary financial statements and records shall be maintained by the Administrator.

- ii. The Chartered Accountancy firm engaged by the Administrator from approved CAG panel for concurrent accounting will also establish accounting formats as per CAG approved Accounting Standards.

III. Audit Arrangements

- i. The Administrator shall engage a Statutory Auditor from among the Chartered Accountancy firms duly empanelled by the Comptroller and Auditor General of India. The engagement of the Statutory Auditor will be approved by the Board of Governors of ICFRE.
- ii. The Administrator shall compile the Annual Accounts of the preceding year of the funds under GCP, not later than June of the succeeding year showing, as per CAG Accounting Standard:
 - i. Annual Account Statement
 - ii. Receipt and payment accounts;
 - iii. Income and expenditure accounts; and
 - iv. Balance sheet
- iii. The Auditor will prepare an annual audit report on the accounts of the GCP, which will general or specific comments as they may consider necessary on the financial prudence of the Administrator and on the results of their audit.
- iv. The audited accounts will be placed before the Board of Governors of ICFRE. A copy of the audited accounts shall be submitted to the Ministry.

This issues with approval of the Competent Authority.



(Dr. Satyendra Kumar)

Director (HSMD)

Email: satyendra.kumar07@nic.in

Tel. No.: 011-20819291

To,

1. Director General, ICFRE, Dehradun
2. PCCFs/HoFFs of all States/UTs

Copy to:

1. Sr. PPS to Secretary/PPS to DGF&SS/
2. AS/JS, In-Charge GCP
3. Addl. DGF(FC)

Annexure III**Green Credit Program – Status of Registration/approval of land parcels and Selection of Land Parcels by CPSUs**

S. No.	State	Registered Land parcels		Land parcels approved by ICFRE		Land Parcels Selected by CPSUs	
		No.	Area (ha)	No.	Area (ha)	No.	Area (ha)
1.	Assam	10	454	10	454	10	454
2.	Bihar	41	3023.72	11	770	11	770
3.	Chhattisgarh	87	1845.92	46	1028	46	1028
4.	Gujarat	342	6761.21	268	5299.25	248	4836.03
5.	Jharkhand	83	2641.73	17	571.05	17	571.05
6.	Madhya Pradesh	229	10648.2	153	7245.29	101	4519.49
7.	Maharashtra	76	1180	70	1113	45	756
8.	Odisha	62	627	21	230	21	230
9.	Rajasthan	16	883	10	390	10	390
10.	Tamil Nadu	159	4236.71	88	1754.95	24	1155.23
11.	Telangana	77	1738.02	69	1564.02	41	1264
12.	Uttar Pradesh	67	883.96	49	525.72	48	518.72
13.	Uttarakhand	11	200.03	3	57.5	3	57.5
	Grand Total	1260	35123.5	815	21002.78	625	16550.02

District-wise Land parcel status for the state of Bihar as on 16th July 2024

S.No	Registration No	District	Total Area (ha)	Status
1	406	Aurangabad	85.00	Rejected
2	407	Aurangabad	75.00	Rejected
3	352	Aurangabad	85.00	Rejected
4	1248	Banka	55.18	Approved
5	1247	Banka	55.18	Approved
6	289	Banka	110.00	Rejected
7	320	Banka	55.00	Rejected
8	322	Banka	55.00	Rejected
9	342	Banka	110.00	Rejected
10	362	Banka	110.00	Rejected
11	368	Banka	55.18	Rejected
12	369	Banka	55.18	Rejected
13	1246	Banka	110.00	Approved
14	1403	Gaya	105.00	Under Query
15	1404	Gaya	108.00	Under Query
16	317	Gaya	100.00	Rejected
17	319	Gaya	100.00	Approved
18	363	Gaya	100.00	Rejected
19	284	Jamui	100.00	Rejected
20	285	Jamui	80.00	Rejected
21	1222	Jamui	100.00	Approved
22	1345	Kaimur	51.00	Approved
23	1406	Kaimur	50.00	Under Query
24	1405	Kaimur	70.00	Under Query
25	312	Kaimur	100.00	Approved
26	313	Kaimur	35.00	Rejected
27	244	Munger	50.00	Approved
28	243	Munger	100.00	Approved
29	1268	Nawada	62.00	Under Query
30	245	Nawada	62.00	Rejected
31	246	Nawada	68.00	Rejected
32	247	Nawada	55.00	Rejected
33	353	Nawada	62.00	Rejected
34	354	Nawada	70.00	Rejected
35	355	Nawada	55.00	Approved
36	360	Nawada	70.00	Rejected

37	1267	Nawada	55.00	Approved
38	282	Rohtas	50.00	Approved
39	30	Rohtas	50.00	Rejected
40	283	Rohtas	50.00	Rejected
41	370	Rohtas	50.00	Rejected